/font>

Title: Need to contain the price of LPG and Kerosene - Laid.

**डॉ0 सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में रसोई गैस व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचे जाने वाले कैरोसिन तैल पर सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। देश की तेल कम्पनियों का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं के बेचने से उनको वर्ा 2002-2003 में 3000 करोड़ रूपए की हानि हो चुकी है, इसलिए आज जब खुले बाजार की नीति सरकार द्वारा आमतौर से अपनायी गयी है तो जरूरी है कि उपरोक्त पैट्रोलियम पदार्थो की कीमतें कम से कम 40 प्रतिशत बढ़ायी जायें। एल.पी.जी. अथवा कैरोसिन तेल आज ईंधन के रूप में घरों में जला कर रसोई का काम किया जा रहा है।

महोदय, यदि इनकी कीमतें बढ़ा दी तो लोग लकड़ी की ओर मुड़ जायेंगे। आज पहले से ही देश में जंगलों का अभाव होता जा हरा है और लगातार मोसम का वाता वरण असंतुलित होता जा रहा है। यदि जंगलों पर और दवाब लकड़ी की मांग बढ़ने से आ गया तो देश का पर्यावरण और असंतुलित हो जाएगा और देश और संकट में आ जायेगा।

गत् वर्ा 2002-2003 का बजट पेश करते समय क्रूड ऑयल पर उपकर 900 रूपए से बढ़ाकर 1800 रूपए किया गया, 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क एल.पी.जी. और कैरोसिन पर किया गया, 50 पैसा पेट्रोल डीजल पर उपकर सड़क कोा के लिए लगाया गया, इसके अतिरिक्त 6 रूपया प्रति लीटर पैट्रोल पर सरचार्ज लगाया गया। यह सरचार्ज इसी एल.पी.जी. और कैरोसिन की सब्सिडी की क्षतिपूर्ति के लिए था और अनुमान है कि इस सरचार्ज से देश में चालू वर्ा में 6,550 करोड़ रूपया एकत्रित होगा जो सब्सिडी की राशि से 285 करोड़ अधिक है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त पदार्थो के मूल्य बढ़ाने की बजाय कराधान में संशोधन करें।